

Human Resource Development in BSNL

India is a wonderful democratic country and its great constitution has set the benchmark for running a democratic system. After independence, the national leaders felt that welfare arrangements should be made for the labour community of the country and under this thinking, a separate arrangement for human resource development has been made in all government departments and public sector undertakings over a period of time. A strong arrangement for human resource development has been made in BSNL too and a post of Director has been created for human resource development in the BSNL board and additional officers have been appointed for the development and to implement welfare of human resources in all divisional offices and commercial area offices including the corporate office.

The financial condition of BSNL started declining after the year 2008-09, although the employees and middle class officers of BSNL are not responsible for this decline. BSNL is a service provider public sector undertaking which provides communication services on a national scale under the supervision of high ranking officials under the policies of the Government of India. **On one hand the Government implements non-profit schemes in BSNL while making it a service provider undertaking and on the other hand it cuts down the benefits of its employees to make up for the fall in revenue.**

It is known that the salary revision of BSNL employees is pending since 01.01.2017 and it is not happening because BSNL is not financially capable of following the arrangement for salary revision for public enterprises as per the financial capacity provided by the Department of Public Enterprises, Government of India. Employees and officers kept pleading with the government for 7 consecutive years after 2017. Many satyagra has were done but till now the government has not taken any step in the process of giving relaxation in the criteria of condition imposed by the Department of Public Enterprises for salary revision. It is seen that all the employees and officers of BSNL have become disappointed due to non-resolution of this issue. The government and BSNL management know that more than 50% of the non-executive employees have been deprived of annual salary hike for many years. This is a very difficult situation for the employees. Employees have been working for years without a single annual hike. The government and management are not taking any initiative to solve this problem. When frustrated employees raise their voice under the trade union rights, they are harassed in various ways. But no one pays attention to their legitimate rights.

The situation has become terrible in the matter of promotions as well. In the name of timely promotion, employees have to face salary blockage. Also, competitive examinations are not conducted in all the circles. Employees recruited at the same time and cause to get the opportunity to appear in the examination in some states, whereas in most of the states, employees do not get this opportunity.

The employees are being denied transfer even under the policy that was made for the employees to their desired place. Even employees are not being transferred on the basis of marital status. Employees have been deprived of transport allowance and children's education allowance. The employees of the Government of India are given tourism facilities at government expense. This facility was also available in BSNL for the first few years, but for the last several years, employees have been deprived of this facility.

In the entire BSNL, there is a severe lack of facilities at the workplace of employees working in technical establishments run under most of the regional offices. Employees have to work in a more humane environment. Employee organizations have repeatedly drawn the attention of the management

on all these points but the arrangements made by the management are negligible. The condition of the employee & housing allotted by BSNL has also become dilapidated but lakhs of rupees are spent year after year in the name of repair and painting of the houses of high ranking officials. But despite the dilapidated condition of water and toilets in the employees' housing, the attention of the management does not go towards it. Overall, it seems that BSNL employees are second class citizens. Neither the management nor the government pays attention to these conditions.

It seems that in future the government is making arrangements to keep BSNL alive by using external resources. For every work in BSNL, labourers are hired from outside contractors. They are made to work on low wages, and the management thinks that the company's work is well organised. But the reality on the ground is that the same employees who are deprived of all facilities are rendering their services with full commitment in running the department years together. Due to which even today BSNL is present among the public as a reliable service provider. The management says that even now the company is facing a loss of Rs 500 crores per month. But on the ground, a huge amount is being paid every month as rent to those landlords in whose buildings no work of the company is being done.

In this situation, we expect that the top management to take steps towards resolving the long pending problems of the employees to keep their enthusiasm alive so that the employees can be fully motivated and help in taking the company to greater heights.

संपादकीय

बीएसएनएल में मानव संसाधन विकास

भारत एक अद्भूत लोकतांत्रिक देश है और इसके महान संविधान के द्वारा लोकतंत्र की व्यवस्था चलाने की कसौटी बनाई है। राष्ट्रीय नेताओं ने आजादी के बाद महसूस किया कि देश के श्रमिक समुदाय के लिए कल्याणकारी व्यवस्था की जानी चाहिए और इसी सोच के तहत कालान्तर में सभी सरकारी विभागों में तथा सरकारी लोक उपक्रमों में मानव संसाधन विकास की एक अलग व्यवस्था की गई है। बी.एस.एन.एल. में भी मानव संसाधन विकास के लिये एक सुदृढ़ व्यवस्था की गई है और बी.एस.एन.एल. बोर्ड में निदेशक का एक पद मानव संसाधन विकास के लिये सृजित की गई है तथा निगमित कार्यालय सहित सभी प्रमंडलीय कार्यालयों एवं वाणिज्य क्षेत्र कार्यालयों में मानव संसाधन के विकास कल्याण हेतु अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त है।

बी.एस.एन.एल. की आर्थिक स्थिति वर्ष 2008-09 के बाद शनैः शनैः गिरावट की ओर जाने लगी, हालांकि इस गिरावट के लिए बी.एस.एन.एल. के कर्मचारी और मध्यमवर्गीय अधिकारी जवाबदेह नहीं होते हैं। बी.एस.एन.एल. एक सेवा प्रदाता लोक उपक्रम है जो भारत सरकार के नितियों के तहत उच्च पदस्थ अधिकारियों के देख-रेख में संचार सेवाएँ राष्ट्रीय पैमाने पर प्रदान करती है। बी.एस.एन.एल. को एक तरफ सेवा प्रदाता उपक्रम करते हुए सरकार अलाभकारी योजनाएँ लागू कराती है और दुसरे तरफ राजस्व में गिरावट के लिये कर्मचारियों को उनकी सुविधाओं में कटौती करती है।

ज्ञातव्य है कि बी.एस.एन.एल. कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण 1.1.2017 से लंबित है और यह इसलिए नहीं हो रहा कि भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग द्वारा आर्थिक सामर्थ्य के अनुरूप जो लोक उपक्रमों के लिये वेतन पुनरीक्षण के लिये व्यवस्था दी गई है, बी.एस.एन.एल. को उस अनुरूप आर्थिक रूप से सामर्थ्य नहीं है। कर्मचारी और अधिकारी वर्ष 2017 के बाद लगातार सात वर्षों तक सरकार से गुहार लगाते रहे। अनेकों सत्याग्रह किये परन्तु अभी तक सरकार की ओर से वेतन पुनरीक्षण के लिये लोक उपक्रम विभाग द्वारा थोपी गई सामर्थ्यता की मापदंड में छूट देने के प्रक्रिया में कदम नहीं उठाया गया।

ऐसा देखा जा रहा है कि बी.एस.एन.एल. के समस्त कर्मचारी और अधिकारी इस मुद्दे

का समाधान नहीं होने की स्थिति में मायूस हो चुके हैं। सरकार एवं बी.एस.एन.एल. प्रबन्धन को यह ज्ञात है कि नान-एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों में लगभग पचास प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी कई वर्षों से वार्षिक वेतन बढ़ोत्तरी से वंचित है। यह कर्मचारियों के लिए एक अतिदुरुह स्थिति है। कर्मचारी बिना एक पैसे की वार्षिक बढ़ोत्तरी के वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं।

इस समस्या के समाधान की ओर भी सरकार एवं प्रबन्धन की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है। मायूस कर्मचारी जब ट्रेड यूनियन अधिकारों के तहत आवाज उठाते हैं तो उनको तरह-तरह से प्रताड़ित किये जाता है। परन्तु उनके वाजिव हकों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है।

पदोन्नति का मामले में भी स्थिति भयावह हो चुकी है। समयबद्ध पदोन्नति के नाम पर कर्मचारियों को वेतन अवरूद्धता का सामना करना पड़ता है। साथ ही प्रतिस्पर्धा जनित परीक्षाएँ सभी परिमंडलों में आयोजित नहीं की जाती है। एक ही समय के भर्ती कर्मचारी कुछ राज्यों में परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करते हैं, वहीं अधिकांश राज्यों में कर्मचारियों को यह अवसर प्राप्त नहीं होता है।

कर्मचारियों के लिए अपने इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की जो नीति बनाई गई थी उसके तहत भी कर्मचारियों को

स्थानान्तरण से इन्कार किया जा रहा है। यहाँ तक की दाम्पत्य के आधार पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों को यातायात भत्ता तथा बच्चों की शिक्षा भत्ता से वंचित रखा गया है। भारत सरकार के कर्मचारियों को सरकारी खर्च पर पर्यटन की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा बी.एस.एन.एल. में भी शुरू के कई वर्षों तक मिलती रही परन्तु विगत कई वर्षों से कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है।

पुरे बी.एस.एन.एल. में अधिकांश क्षेत्रिय कार्यालयों के अधीनस्थ संचालित तकनीकी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के दिये कार्यस्थल पर वांछित सुविधाओं का घोर अभाव है। कर्मचारी अमानवीय परिवेश में कार्य करने को बाध्य है। समस्त बिन्दुओं पर कर्मचारी संगठनों ने बार-बार प्रबन्धन का ध्यान आकृष्ट किया है परन्तु प्रबन्धन की ओर से व्यवस्थाएँ नगण्य हैं। बी.एस.एन.एल. द्वारा आवंटित कर्मचारी आवासों की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है परन्तु उच्च पदस्थ अधिकारियों के आवास पर साल दर साल मरम्मती के नाम पर एवं रंगाई पुताई के नाम पर लाखों रुपये व्यय किये जाते हैं परन्तु कर्मचारियों के आवास में जल एवं शौचालयों की स्थिति जर्जर होने के बावजूद प्रबन्धन का ध्यान उस ओर नहीं जाता। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बी.एस.एन.एल. के कर्मचारी द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, ना तो प्रबन्धन और ना ही सरकार इन परिस्थितियों पर ध्यान देती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में सरकार बी.एस.एन.एल. को जीवंत रखने में बाह्य संसाधनों का उपयोग के द्वारा इसे संचालित रखने की व्यवस्था कर रही है। बी.एस.एन.एल. में हर कार्य के लिए बाहरी ठेकेदारों से श्रमिक लिये जाते हैं जिन्हें अल्प वेतन पर कार्य कराया जाता है और प्रबन्धन समझती है कि कम्पनी का कार्य सुचारु रूप से व्यवस्थित है। परन्तु सरजमीन की वास्तविकता यह है कि वहीं कर्मचारी जो हर सुविधाओं से वंचित है विभाग के संचालन में पूर्ण कटिबद्धता से अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। जिससे आज भी बी.एस.एन.एल. जनता के बीच एक विश्वसनीय सेवा-प्रदाता के रूप में उपस्थित है। प्रबन्धन द्वारा कहा जाता है कि अभी भी कम्पनी को प्रतिमाह पाँच सौ करोड़ रुपये की हानी का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु सरजमीन पर उन मकान मालिकों को हर माह भारी रकम किराए के रूप में दी जा रही है, जिन भवनों में कम्पनी का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है।

इस परिस्थिति में हम उच्च प्रबन्धन से आशा करते हैं कि कर्मचारियों के उत्साह को बचाये रखने के लिए उनके चीर लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाए ताकि कर्मचारी पूर्ण रूप से उत्साहित होकर कम्पनी की उँचाईयों तक ले जाने में सहयोग कर सकें।